

संपादकीय

खिलाफ़-मत्थान

संपादकीय

सबसे स्वच्छ शहर में जहरीला पानी, तमगे नहीं, जानज्यादा जरूरी

दूषित पेयजल की मार से प्रभावित इलाजके में स्थानीय लोगों ने पिछले देव वर्ष से इससे होने वाली परेशानी और शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने की बात कही। विचित्र और अक्सरोंसानक है कि जिस शहर को पिछले कई वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमाम पिल रहा हो, वहां दूषित पेयजल के सेवन से लोगों के मरने की खबर आती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और करीब दो सौ लोगों को अस्पताल भर्ती होना पड़ा। खबरों के मुताबिक, भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में गंदा पानी मिल गया, जिससे पानी दूषित हो गया। लोगों ने इस पानी का सेवन शायद इसलिए भी कर लिया कि साफ और गंदे पानी में फर्क करना मुश्किल हो गया था। सवाल है कि अगर आम लोग पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति पर निर्भर हों, तो उनके पास गंदा और दूषित पानी पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है। लोगों की मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने गलती मानते हुए आनन्दानन्दन में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन यह साफ है कि संविधित महकों की नीत तभी खुलती है, जब काई बड़ा नुकसान हो चुका होता है यां, देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और इस क्रम में उनकी सहन के साथ क्या होता है, इसकी परवाह शायद किसी को नहीं है। खबरों के मुताबिक, दूषित पेयजल की मार से प्रभावित इलाके में स्थानीय लोगों ने पिछले देव वर्ष से इससे होने वाली परेशानी और शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने की बात कही। मगर सरकार के कामकाज के अदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पेयजल में दूषित पानी शीतों की बात का पवार परिवार है, जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया दिसके अलावा, पीने के पानी के पाइप लाइन से अलग गंदे पानी के निकासी की लाइन को सुरक्षित मानकों तक दूर रखने की व्यवस्था नहीं की गई, तो इसकी क्या बाब जह हो सकती है? क्या यह सिर्फ अक्षम अधिकारियों की अदूरदर्शिता का मामला है या फिर जानबूझ कर की गई अनदेखी की? इस तरह की लापरवाही का इलाज सिर्फ कुछ औपचारिक कदम नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी स्तर पर सजगता और जिम्मेदारी की जरूरत है विडंबना यह है कि सरकार का मकसद प्रचार के लिए किसी शहर की स्वच्छता के तमगे हासिल करना रह गया लगता है। सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में अगर कुछ लोगों को जहरीला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा, तो इस विरोधाभासी हकीकत की पड़ताल करने की जरूरत है कि ऐसे तमगे जारी किए जाने के पैमाने क्या है? पीने का पानी सबसे बुनियादी जरूरत है, जिसके बिना ज्यादा वक्त तक नहीं रहा जा सकता सरकार देश भर में हर घर नल से जल पहुंचने की योजना के तहत सबको स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का दाव करती है। मगर इस दावे की हकीकत अवसर समान आती रहती है, जब किसी इलाके में भूजल सूख जाने तो कहीं पीने के पानी के लिए लोगों के जोड़जहां करने की खबरें आती हैं। जहां पेयजल अपूर्ति की व्यवस्था हो भी, अगर वहां यह सेवन पर जोखिम से लेकर जानलेवा होने तक के खतरे से बची नहीं है, तो इसे कैसे देखा जाएगा। यह समझना मुश्किल है कि कमियों पर ध्यान देने और पेयजल के पाइप लाइन के सुरक्षित होने की निगरानी नियमित जवाबदेही में शामिल रह्यों नहीं होती, ताकि ऐसी त्रासदी से बचा जा सके।

उमर खालिद के समर्थन में उत्तर कर मामदानी ने बड़ा खतरनाक खेल खेला है

(नीरज कुमार दुबे)

इस पर के सम्मन अने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आलोचकों को कहना है कि किसी विदेशी शहर के मेयर द्वारा भारत के एक संवेदनशील कानूनी मामले में पक्ष लेना अनुचित है। खासकर तब, जब मामला दोगों और भारत के एक संवेदनशील कानूनी मामले में पक्ष लेना अनुचित है। खासकर तब, जब मामला दोगों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। न्यूराक के मेयर जोहरान मामदानी की ओर से भारत में लिहाड़ जेल में बंद उपर खालिद को भेजे गए एक पत्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खालिद के विचारों की तरीफ करते हुए दिखाया कि वे उनके बारे में सोच रहे हैं। लंगेनीय है कि उमर खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दोंगे से जुड़े गंभीर आरोपों की सुनवाई चल रही है। इस पत्र के सामने आने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

मिली है। आलोचकों का कहना है कि किसी विदेशी शहर के मेयर द्वारा भारत के एक संवेदनशील कानूनी मामले में पक्ष लेना अनुचित है। खासकर तब, जब मामला दोगों और भारत के एक संवेदनशील कानूनी मामले में पक्ष लेना अनुचित है। आलोचकों को खालिद के रूप में देखा जाता है कि उमर खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दोंगे से जुड़े गंभीर आरोपों की सुनवाई चल रही है। इस पत्र के सामने आने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

लगे तो संप्रभुता और संस्थान देखने के लिए संजीवनी का काम करता है जो अराजकता और टकराव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। मामदानी को यह समझना चाहिए कि भारत का आंतरिक कानून और व्यवस्था किसने दिया कि वह भारत के दोगों से जुड़े एक आरोपी की तरीफ करे और उसे नैतिक समर्थन दे। एक आरोपी को समझना होगा कि चप्पल रखने से नैतिक समर्थन देना कोई साधारण समाजिक कार्यकर्ता नहीं है और अपने फैसले खुद लेने में समर्थ है। उमर खालिद के दोगों के नैतिक समर्थन देना के बावजूद भारत के लिए गलत है, तो उन्हें कुछ भी हात नहीं लगेगा। यहां यह बताना जरूरी है कि एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन में भी लगता है। बारामती में हाल ही में रहने पर वरिवार के बारे में योग्य कानूनी विवरण देखने के लिए गलत है, तो उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया के अंदर खालिद के दोगों के नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पर्सनों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका भी गलत है। एक दौर में बीमसीरी पर शिक्षन का बजाय नैतिक समर्थन देना के आरोपी की तरीफ करने के बावजूद उन्हें जारी करना चाहिए। भारत में व्याय की प्रक्रिया

